जबलपुर में साइबर ठगी के ६ मामले, शिक्षक सहित कई लोगोंके खातेसे ५.३० लाख रुपये पार

मीशो से मंगाए स्कूल बैग के रिफंड के नाम पर महिला से ९८ हजार की ठगी, शिक्षक के खाते से निकले १.०७ लाख रुपये

जबलपुर, (एजेंसी)। शहर में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। माढ़ोताल और अधारताल थाना क्षेत्रों में दर्ज ६ मामलों में साइबर ठगों ने लोगों के बैंक खातों से कुल साढ़े ५ लाख रुपये से अधिक की रकम पार कर दी। ठगी के शिकार लोगों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा ३१८(४) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एपीके फाइल डाउनलोड होते ही निकली रकम

गौरीघाट थाना क्षेत्र के ललपुर स्थित शिवराज सिंह नगर नई बस्ती निवासी २९ वर्षीय रोहित लांजेवार ऑटो चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि २२ अक्टूबर को उनके मोबाइल में अज्ञात स्रोत से एपीके फाइल डाउनलोड हो गई थी। इसके बाद मोबाइल की स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर अपडेट का विकल्प दिखाई देने लगा। कई घंटे बाद भी यह विकल्प नहीं हटा तो उन्होंने मोबाइल चालू कर जांच की। इस दौरान पता चला कि गूगल पे के माध्यम से ४८ हजार रुपये और फोन के जरिए १५ हजार ६०० रुपये उनके अलग-अलग खातों से निकाल लिए गए हैं। अज्ञात व्यक्ति ने सायबर ठगी कर कुल ६३ हजार ६०० रुपये हड़प लिए। शिकायत पर ग्वारीघाट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१८(४) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

आनलाइन धोखाधड़ी कर ६४ हजार उड़ाए

दूसरा मामला माढ़ोताल थाना क्षेत्र का है। अमगवां, थाना सिहोरा निवासी और वर्तमान में न्यू बस्ती आईटीआई माढ़ोताल में रहने वाली २४ वर्षीय पूर्वी कुर्मी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने किसी अन्य का रूप धारण कर उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की और ६४ हजार २२९ रुपये हड़प लिए। शिकायत पर माढ़ोताल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१८(४), ३१९(२) और ३०८ के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धमकी देकर ३० हजार रुपये की ठगी

माढ़ोताल थाना क्षेत्र की ग्रीन सिटी निवासी ३० वर्षीय आकाश कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ वित्तीय धोखाधड़ी की और ३० हजार रुपये हड़प लिए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

शिक्षक के खाते से १.०७ लाख रुपये गायब

अधारताल थाना क्षेत्र में बिजासन माता मंदिर के सामने रहने वाले ४७ वर्षीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा, जो शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनागर में शिक्षक हैं, के बैंक खाते से १ लाख ७ हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। उन्होंने बताया कि २१ अक्टूबर को दोपहर ३:१० बजे खाते से ९७ हजार रुपये और २२ अक्टूबर को १० हजार रुपये निकल गए। बैंक से जानकारी लेने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

रिफंड के नाम पर महिला को लगाया चूना

अधारताल के सुभाषनगर महाराजपुर निवासी ४८ वर्षीय सविता मायकल ने मीशो से स्कूल बैग मंगाए थे। २३ अक्टूबर को डिलीवरी के दौरान उन्होंने गूगल पे के माध्यम से ५३० रुपये का भुगतान किया, जबकि बैग की कीमत ५२६ रुपये थी। चार रुपये अधिक लिए जाने की शिकायत करने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर मीशो हेल्पलाइन का नंबर तलाश कर संपर्क किया। बातचीत के दौरान कथित तौर पर बैलेंस चेक करने के लिए कहा गया। इसके बाद उनके खाते से ९० हजार और ८ हजार रुपये, कुल ९८ हजार रुपये, अरुण कुमार रविदास के खाते में ट्रांसफर हो गए।

राघौगढ़ के सावत खेड़ी में दर्दनाक हादसा खेत पर मोटर चालू करने गए २७ वर्षीय युवा किसान की करंट लगने से मौत

गुना, (एजेंसी)। जिले के राघौगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावत खेड़ी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। खेत पर पानी की मोटर चालू करने गए २७ वर्षीय युवा किसान की करंट की चपेट में आने से अकाल मौत हो गई। इस अचानक हुए हादसे से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृत किसान पन्नालाल यादव (२७ वर्ष) पुत्र घुमान सिंह यादव रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे गांव के पास स्थित खेत पर बने कुएं पर पानी की मोटर चालू करने के लिए गया था। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा, तो उसके छोटे बच्चों ने वहां जाकर देखा और परिजनों को करंट लगने की सूचना दी। खबर मिलते ही बड़े भाई मलखान सिंह व अन्य स्वजन आनन-फानन में गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और अचेत अवस्था में पन्नालाल को अस्पताल लेकर आए, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद से मृतक के दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और परिवार के सामने भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पार्थिव देह परिजनों को सौंप दी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

बैंक की औपचारिकताओं में उलझे २५९ किसान

सोलर पंप योजना का लाभ मिलने में देरी नए पंजीयन के लिए पोर्टल खोलने की मांग

जबलपुर, (एजेंसी)। बिजली की कमी के बीच सिंचाई के लिए सोलर कृषि पंप किसानों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरे हैं, लेकिन योजना की जटिल औपचारिकताओं और दस्तावेजों में विसंगतियों के चलते पात्र किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा चयनित २५९ किसानों के सोलर पंप स्थापना संबंधी प्रकरण बैंक में लंबित हैं। भारत कृषक समाज ने इन बाधाओं को दूर कर रबी सीजन से पहले किसानों के खेतों में सोलर पंप स्थापित कराने की मांग की है।

योजना के तहत किसानों को कुल लागत की १० प्रतिशत राशि मार्जिन मनी के रूप में जमा करनी है, जबकि शेष ९० प्रतिशत राशि किसान के नाम पर बैंक से ऋण के रूप में स्वीकृत कराई जानी है, जिसका भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। कृषक समाज के अनुसार, किसानों ने ३१ मार्च के पहले अपनी मार्जिन मनी जमा कर दी थी। इसके बावजूद बैंक और पोर्टल से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण अनेक किसानों के प्रकरण अटके हुए हैं।

किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए भारत कृषक समाज के पदाधिकारियों ने पिछले माह सिविक सेंटर स्थित ऊर्जा विकास निगम कार्यालय में अधिकारियों से चर्चा की थी। इसके बाद किसानों को बैंक की औपचारिकताएं पूरी कराने और वेंडर एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी सिलसिले में कृषक समाज के के.के. अग्रवाल, रामकिशन पटेल और व्ही.के. पंडया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिलवाराघाट शाखा के प्रबंधक शैलेन्द्र कुमार से मुलाकात कर लंबित प्रकरणों पर चर्चा की।

शाखा प्रबंधक ने बताया कि किसानों के दस्तावेजों और ऑनलाइन विवरण में विसंगतियों के कारण ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई किसानों के आधार कार्ड और बैंक खातों में दर्ज नामों का मिलान नहीं हो रहा है। नाम की वर्तनी में मामूली अंतर होने से भी ओटीपी और डिजिटल सत्यापन में परेशानी आ रही है। किसानों को संबंधित बैंक शाखा में जाकर केवाईसी और सीआईएफ संबंधी विवरण दुरुस्त कराने की सलाह दी गई है।

इसी तरह ऊर्जा विभाग के पोर्टल पर कुछ किसानों के नाम गलत दर्ज हैं। ऐसे किसानों को आवेदन क्रमांक के आधार पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विवरण की जांच कराकर सुधार कराना होगा। पोर्टल और बैंक में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज होने से भी ओटीपी प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। इसके अलावा किसानों को चयनित वेंडर कंपनी से संपर्क कर एआईएफ संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक द्वारा ई-साइन के लिए लिंक भेजी जाएगी, जिसे पूरा करना आवश्यक है।

भारत कृषक समाज का कहना है कि अधिकांश लाभार्थी छोटे किसान हैं और वे ऑनलाइन प्रक्रियाओं तथा तकनीकी औपचारिकताओं से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। उचित मार्गदर्शन के अभाव में उन्हें बैंक और पोर्टल संबंधी कार्य पूरे करने में परेशानी हो रही है। यदि समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो पात्र किसान रबी सीजन में सोलर पंप योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। कृषक समाज ने कलेक्टर से मांग की है कि किसानों की बैंक संबंधी औपचारिकताएं पूरी कराने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो सके और निर्धारित समय में सोलर पंप स्थापित किए जा सकें।

संगठन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ई-मेल से भेजे पत्र में बिजली की कमी को देखते हुए सोलर कृषि पंप योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। साथ ही नए किसानों के पंजीयन के लिए पोर्टल शीघ्र खोलने और पहले से पंजीकृत किसानों के यहां पंप स्थापना में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने की मांग की है।

८,२६४ उम्मीदवारों के १०वीं में १०० प्रतिशत अंक दर्ज

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में बड़ी धांधली का खुलासा, मध्य प्रदेश से यूपी तक चयन सूची में चौंकाने वाले आंकड़े

भोपाल, (एजेंसी)। डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में १०वीं के अंकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस साल चयनित अभ्यर्थियों में ८,२६४ उम्मीदवारों के १०वीं में १०० प्रतिशत अंक दर्ज किए गए हैं। चयन सूची में पूर्णांक पाने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या ने भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की सत्यता और सत्यापन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में चयनित १,४५० अभ्यर्थियों में से १,१५५ के १०वीं में पूरे अंक दर्ज हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में चयनित १,६८७ उम्मीदवारों में से १,६१६ ने १०० प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भर्ती में इस्तेमाल की गई अंकसूचियों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में पिछले सात वर्षों के दौरान १०वीं की बोर्ड परीक्षा में केवल १६ विद्यार्थियों ने पूर्णांक हासिल किए, जबकि मौजूदा ग्रामीण डाक सेवक चयन सूची में ऐसे १,१५५ नाम शामिल हैं। हालांकि, इन आंकड़ों और अलग-अलग बोर्डों के परिणामों की आधिकारिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से होना जरूरी है।

अंकसूचियों में कथित गड़बड़ी की जांच

विभागीय सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ वर्षों से शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों, बिचौलियों और डाक विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कथित तौर पर संदिग्ध अंकसूचियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, गड़बड़ी सामने आने पर कुछ नियुक्तियों को समाप्त करने की कार्रवाई भी की गई है। जबलपुर डाक सर्किल में बिहार बोर्ड की अंकसूचियों के आधार पर चयनित आठ कर्मचारियों को पिछले महीने बर्खास्त किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इन मामलों में दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच का अहम विषय बनी हुई है।

सीबीआई की कार्रवाई से मामले ने पकड़ा जोर

रिपोर्ट के अनुसार, कथित फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किया है। एजेंसी ने ३० सितंबर को मुरैना से मानवेंद्र सिंह सिकरवार, रमाकांत शर्मा, सौरभ शर्मा और प्रदीप खरे को गिरफ्तार किया। इसके अलावा सागर, देवास और टीकमगढ़ से जुड़े चार अन्य लोगों के फरार होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

आनलाइन भर्ती और दस्तावेज सत्यापन पर सवाल

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और इसमें देश के किसी भी राज्य का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। चयन में १०वीं के अंकों की अहम भूमिका होती है, जबकि नियुक्ति से पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। मध्य प्रदेश के डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस आरएस रघुवंशी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में पूर्णांक पाने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है। अब जांच में यह स्पष्ट होना अहम होगा कि संदिग्ध अंकसूचियां किन बोर्डों से जारी हुईं, सत्यापन के दौरान कथित गड़बड़ी कैसे सामने नहीं आई और इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका रही।

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के मुंह पर कालिख पोती

जिला अनुसूचित जाति मोर्चाने चंद्रशेखर तिवारी का मुंह काला किया अनुसूचित जातिके लिए जातिसूचक शब्दोंका इस्तेमाल करने का आरोप

भोपाल, (एजेंसी)। पुराने शहर के भवानी चौक (पीर गेट) पर सोमवार दोपहर को उस समय हंगामा मच गया जब हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ कुछ युवकों ने झूमाझटकी करते हुए उनके मुंह पर स्याही (कालिख) पोत दी। जानकारी के मुताबिक तिवारी पर बीते दिनो एक इंटरव्यू के दौरान अनुसूचित जाति के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। विवाद के बाद उन्होंने इसे गलती बताते हुए वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी। ३ दिन पूर्व एससीएसटी समुदाय को लेकर किये गये आपत्तिजनक बयान पर आक्रोशित जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश अहिवार के नेतृत्व में सोमवार को पीर गेट पर हंगामा करते हुए आक्रोशित होकर चंद्रशेखर तिवारी के चेहरे पर स्याही पोत डाली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। घटना के बाद तिवारी ने वीडियो जारी कर कहा की आरोप लगाया कि हमला करने वाले युवकों ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। तिवारी ने कहा कि सनातन धर्म को तोड़ने वालों के सामने वे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, तुमने गर्दन काटने की धमकी दी है। जब तक गर्दन नहीं काटोगे, तब तक सनातन का काम करता रहूंगा। मैं हिंदू समाज का था, हिंदू समाज का हूं और हिंदू समाज का रहूंगा। उन्होंने हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। हालांकि घटना को लेकर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में दावा किया जा रहा हैं, बीते दिनो झांकियों के दौरान डीजे पर की गई सख्ती को लेकर तिवारी ने उचित कार्यवाही नहीं की। इसी से नाराज लोगों ने उनके मुंह पर कालिख पोती। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने की कार्रवाई को लेकर तिवारी की समझाइश दे रहे मंगलवारा थाना प्रभारी से तीखी बहस हुई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें तिवारी शहर को जलाने तक की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे।

'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को बूथ स्तर तक ले जाएगी कांग्रेस

१ नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली

जबलपुर, (एजेंसी)। मतदाता सूची की शुद्धता, पात्र नागरिकों के मताधिकार की रक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान को देशव्यापी स्तर पर व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। अभियान के तहत एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश से लेकर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय कर मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों को सामने लाने की कार्ययोजना बनाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मप्र प्रभारी सांसद कल्याण काले ने यहां पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा घोषित इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे।

मध्य प्रदेश में ३४ लाख से अधिक नाम हटाए गए

कांग्रेस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मध्य प्रदेश में ५ करोड़ ७४ लाख ६ हजार १४३ मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या घटकर ५ करोड़ ३१ लाख ३१ हजार ९८३ रह गई, जबकि अंतिम मतदाता सूची में ५ करोड़ ३९ लाख ८१ हजार ६५ मतदाता दर्ज किए गए। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कुल ३४ लाख २५ हजार ७८ नाम हटाए जाने की जानकारी दी गई है।

गांवों में चौपाल, घर-घर पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और बूथ स्तर के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। २५ अक्टूबर से २५ नवंबर तक गांवों में चौपाल, घर-घर संपर्क और संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से मतदाता सूचियों की जांच की जाएगी।

१ नवंबर को दिल्ली में महारैली

श्री काले ने बताया कि कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली में विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची में पारदर्शिता, पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे।

२५-२६ नवंबर को 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम

अभियान के अगले चरण में संविधान दिवस के अवसर पर २५ और २६ नवंबर को 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को २५ नवंबर को ग्वालियर में एकत्रित करने और २६ नवंबर को दिल्ली के लिए रवाना करने की तैयारी है। कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा और यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं पार्टी के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार तय की जाएंगी। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव, विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, आदि उपस्थित थे।

ओशो अनुयायियों की मांग : जबलपुर का नाम हो ओशोपुरम

जबलपुर, (एजेंसी)। अपने जीवन काल में आचार्य रजनीश ने सबसे ज्यादा वक्त संस्कारधानी में ही किया व्यतीत, संस्कारधानी से जुड़ी हैं उनकी अनमोल स्मृतियां, स्वामी श्रीला प्रेम पारस ने कहा कि ओशो जैसा ब्रांड एम्बेसडर इस शहर को अगले १०० वर्षों में नहीं मिल सकताओशो ५८ साल ३९ दिन देह में रहे। ९ वर्ष की आयु में स्कूल जाने लगे। १७ साल में प्राइमरी से एम. ए. तक पढ़ाई की।९ साल कॉलेज में पढ़ाया। अनुमान है कि एक साल ट्रेन में,१ साल व्यक्तिगत मिलने में बीते। हिंदी व इंग्लिश में ६५० पुस्तकें लिखीं। वॉनगॉग से भी बढ़कर१००० पेंटिंग्स बनाईं। ग़ज़लें व पक्के राग सुनते रहे , मिलने वालों से मिलतेरहे व रोज टहलते रहे। सर्वाधिक समय जबलपुर में २० वर्ष रहे , विद्यार्थीकी तरह, प्रोफेसर की तरह, साढ़े तीन साल स्वतंत्र रहे। ओशो का जबलपुर के लिए प्रेम किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में ओशो अनुयायियों के आलावा वॉलीवुड के प्रख्यात डायरेक्टर सुभाष घई और वॉलीवुड के कलाकारों ने भी ओशो के नाम से ही जबलपुर का ओशोपुरम करने की मांग की है। ओशो के करीबी रहे स्वामी अगेह भारती ने बताया कि जब ओशो ने संन्यास देना शुरू किया, उसके ४ साल पहले से वे उनके शिष्य हैं, यदि इस शहर का नाम ओशोपुरम हो जाए तो यह काशी, वृन्दावन, अयोध्या हो जाएगा। पर्यटकों की संख्या तो बेहिसाब बढ़ेगी, नगर का सम्मान सारे विश्व में बढ़ेगा। ओशो होम आश्रम के स्वामी श्रीला प्रेम पारस का कहना है कि ओशो के अनुयायी देश दुनिया में हैं, इस शहर से ओशो की कई अहम स्मृतियां जुड़ीं हैं। आपको बता दें कि देवताल से लेकर भंवरताल और महाकौशल कॉलेज में ओशो की स्मृतियां देखने लोग दूर दूर से जबलपुर पहुंचते हैं।

ब्रेल लिपि से मतदान कर रहे दृष्टिबाधित मतदाता

जबलपुर, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की शाखा का चुनाव लोकतांत्रिक परंपराओं और पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। पांच वर्ष में होने वाले इस चुनाव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए दृष्टिबाधित मतदाता भाग ले रहे हैं। मतदान के लिए ब्रेल लिपि में पांच पृष्ठों का मतपत्र तैयार किया गया है, जिससे मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। चुनाव प्रक्रिया दिल्ली से आए तीन सदस्यीय चुनाव आयोग और स्थानीय सदस्यों की निगरानी में संचालित हो रही है। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. शिवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि आयोजन में अंतरराष्ट्रीय मानव मिलन संस्था ने विशेष सहयोग देते हुए ६०० बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया।

देवी जागरण और भंडारे में खूनी संघर्ष, २ महिलाओं सहित ८ घायल

बुलेट की रफ्तार धीमी करने को कहा तो हथियारों से लैस युवकों ने किया हमला

जबलपुर, (एजेंसी)। रांझी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रविवार रात देवी जागरण और भंडारे के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। भंडारे में भीड़ के बीच तेज रफ्तार से बुलेट निकालने पर युवकों को टोका गया तो करीब १५ से २० मिनट बाद ६ से ७ युवक लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर लौटे और लोगों पर हमला कर दिया। घटना में दो महिलाओं समेत आठ लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुख्य आरोपी समीर वंशकार सहित अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

भीड़ के बीच तेज रफ्तार से निकाली बुलेट

जानकारी के मुताबिक, रविवार रात आजाद नगर में दुर्गा उत्सव के समापन पर देवी जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान बुलेट सवार दो युवक भीड़ के बीच से तेज रफ्तार में निकले। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाइश दी कि आयोजन में बच्चे और महिलाएं भी हैं, इसलिए बाइक धीमी चलाएं। इसी बात को लेकर दोनों युवकों की लोगों से बहस हो गई। विवाद के बाद युवक वहां से चले गए।

१५ मिनट बाद हथियार लेकर लौटे, मची अफरा-तफरी

आरोप है कि कुछ देर बाद ६ से ७ युवक लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुई मारपीट से आयोजन स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हमले में रवि गोटिंया, रागिनी गोटिंया, पप्पू वर्मा, अनुज कोल, पारस यादव, आदि गोटिंया, बिट्टू झारिया और मनीषा गोटिंया घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बीच-बचाव करने पहुंचे लोग भी बने निशाना

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के मुताबिक, शुरुआती जांच में समीर वंशकार का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पहले चार लोगों के साथ मारपीट की गई। उन्हें बचाने के लिए दूसरे लोग आगे आए तो हमलावरों ने उन्हें भी निशाना बनाया। इस दौरान धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

नगर निकायों की ११३४ करोड़ की खरीदी पर सवाल, साइबर सुरक्षा में सेंध का भी खतरा!

जबलपुर, (एजेंसी)। प्रदेश के ३७४ नगर निकायों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ११३४ करोड़ रुपये की खरीदी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। खरीदी में कथित अनियमितताओं के साथ नगर निकायों के सिस्टम में २५०० ई-मेल पते, यूजर आईडी और पासवर्ड सामने आने का मामला केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे साइबर सुरक्षा को लेकर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

लोकायुक्त जांच की अवधि और दायरे पर उठाए सवाल

मंच की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि मामले की जांच २३ अक्टूबर २०२६ को लोकायुक्त को सौंपी गई है। संगठन ने आशंका जताई है कि यदि जांच सभी संभागों में एक साथ और समयबद्ध तरीके से नहीं की गई, तो इसके निष्कर्ष तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। पत्र में साइबर सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी अलग से जांच कराने पर जोर दिया गया है।

एसआईटी जांच और दोषियों पर एफआईआर की मांग

संगठन ने मांग की है कि प्रदेश के प्रत्येक संभाग में एसआईटी गठित कर नगर निकायों में हुई खरीदी की जांच कराई जाए। साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े मामले की शीघ्र जांच कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव, लोकायुक्त और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजे जाने की जानकारी दी गई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के साथ भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, महिला समिति और पेंशनर्स सहित विभिन्न संगठनों ने मामले को लेकर आवाज उठाई है। डॉ. पी.जी. नाजपांडे, रजत भार्गव, टी.वेे. रायचंदक, सुभाषचंद्र, एडवोकेट वेदप्रकाश अधौलिया, सुशीला कनोजिया, गीता पांडे, डी.आर. लखेरा, अशोक यादव, यशवंत कोष्टा और श्याम सोलंकी ने नगर निगमों में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। संगठनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वित्तीय अनियमितताओं और साइबर सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जिम्मेदारी तय की जाए तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

हमीरपुर में दर्दनाक हादसा: बिजली का खंभा लगाते समय करंट की चपेट में आने से लाइनमैन मनीष कुशवाहा की मौत

गुना, (एजेंसी)। जिले के हमीरपुर गांव में बिजली का खंभा गाढ़ते समय एक भीषण हादसा सामने आया है। शटडाउन लेने के बावजूद दूसरे ऑपरेटर द्वारा अचानक विद्युत लाइन चालू कर दिए जाने के कारण करंट की चपेट में आने से ५-६ दिन से काम कर रहे श्रमिक मनीष कुशवाह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं सोमवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

परमिट लेकर किया जा रहा था कार्य

मृतक के पिता श्रीलाल कुशवाह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब ८ बजे उनकी मनीष से बात हुई थी, जिसमें भतीजी के पूछने पर उसने दो दिन बाद घर आने की बात कही थी। इसके बाद वह खेत पर चले गए थे, तभी थोड़ी देर बाद फोन आया कि गाड़ी लेकर तुरंत हमीरपुर पहुंचो साथ काम कर रहे साथियों और परिजनों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा पांच लोगों को खंभा गाढ़ने के कार्य के लिए भेजा गया था। काम शुरू करने से पहले सुबह ९ बजे नियमानुसार शटडाउन (परमिट) लिया गया था, ताकि सुरक्षित तरीके से कार्य किया जा सके। इस दौरान उन्होंने एक खंभा सफलतापूक खड़ा भी कर दिया था।

आपरेटर की लापरवाही से गई जान

परिजनों ने आरोप लगाया कि काम करने वाले श्रमिकों ने लाइनमैन से कहकर विधिवत लाइन बंद करवाई थी, लेकिन उसी दौरान दूसरे ऑपरेटर ने बिना जानकारी के लाइन चालू कर दी। जैसे ही खंभा गाड़ने का कार्य चल रहा था, अचानक हाई-वोल्टेज करंट प्रवाहित होने से मनीष उसकी चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

रीवा के परमाणु प्लांट पर सिंघार की आपत्ति

नेता प्रतिपक्ष बोले- प्लांट से कैंसर फैलेगा, क्या सरकार लोगों को मारना चाहती है

भोपाल, (एजेंसी)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रीवा के सरई गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार को भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार कैंसर के लिए पावर प्लांट डालना चाहती है? क्या आसपास के लोगों को मारना चाहती है? सिंघार ने परियोजना की साइट बदलने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इसके लिए गरीब आदिवासियों, दलितों और किसानों को उजाड़ने की तैयारी है।

सिंघार के मुताबिक प्रस्तावित बिजलीघर के लिए सरकारी जमीन के अलावा करीब १५० हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से जल सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कलेक्टर पर भी ग्रामीणों को हटाने की धमकी देने का आरोप लगाया। सिंघार ने बिजलीघर के लिए बोरिंग की अनुमति से जुड़े पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पंचायत की अनुमति मिलने की बात कह रही है, जबकि ग्रामसभा ने अनुमति देने से इनकार किया है। उनके अनुसार, सरपंच कोमल संजय सिंह ने आयुक्त और कलेक्टर को पत्र लिखकर संबंधित दस्तावेज को फर्जी बताया है। सिंघार ने कहा कि ना मैंने साइन करी, ना मैंने एनओसी दी। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की।

विमला कोल की मौत पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब

जल सत्याग्रह के दौरान विमला कोल की मौत का मुद्दा उठाते